in consultation with the State Authorities. These include 4 major inter-State irrigation projects namely, Tillari, Upper Tapi Stage-II, Lower Penganga and Lendi.

(d) The anticipated expenditure on Lendi Project up to end of Sixth Plan (1984-85) is Rs. 47 lakhs. The likely outlay in VII Plan is Rs. 1 crore, against the estimated cost of Rs. 39.12 crores.

(e) The Lendi project will be cleared after its techno-economic viability is established, the inter-State issues resolved and clearance from environmental angle is obtained. The progress of the work is dependent on the allocation of funds by the State Government.

राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान

2062. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वार्षिक आय में कृषि क्षेत्र का योगदान, जो पहले 36.9 प्रतिशत था, 1984–85 में घटकर केवल 25.5 प्रतिशत रह गया है तथा 1999–2000 तक यह योगदान कितना होगा; और

(ख) क्या सरकार इसे एक उद्योग मानकर चलाना चाहती है या कृषि क्षेत्र का विकास करके और उसे आधुनिक बनाकर कृषि आय के आधार पर अन्य उद्योग शुरू करने का विचार रखती है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 1970-71 के मूल्यों के अनुसार निवल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 1982-83 तथा 1983-84 में क्रमश: 39.1 तथा 39.7 प्रतिशत था। 1984-85 के लिए इसी प्रकार के अनुमान अभी केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा निर्मुक्त नहीं किए गए हैं। तथापि, सातवीं योजना दस्तावेज के अनुसार राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 1984-85 में 36.86 प्रतिशत होने का अनुमान है, और 1984-85 के मूल्यों के अनुसार 1999-2000 ई० तक 25.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ख) कृषि उत्पादन काफी हद तक मौसम तथा वर्षा पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र में उत्पादन लाखों किसानों द्वारा किया जाता है। कृषि उत्पाद प्राकृतिक रूप से विषमांगी और खराबी हो जाने वाला है, कृषि उत्पादन की विशिष्ट परिस्थितियों और इसके उत्पादों के लक्षणों/प्रकृति के कारण कृषि को एक उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता तथापि, सरकार कृषि क्षेत्र तथा कृषि पर आधारित उद्योगों का योजनाबद्ध प्रयासों से विकास तथा आधुनिकीकरण करने के लिए बराबर कोशिशें कर रही है।

Allotment of flats under the IV Self-Finance Scheme in Sidharth Extension, New Delhi

2063. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a draw of lot was held for allotment of Category II houses under DDA's IV Self-Finance Scheme in Sidharth Extension, South Delhi;

(b) if so, the date of the draw of lot;

(c) whether it is a fact that so far no flats have been allotted to the successful allottees;

(d) if so, what are the reasons therefor ;

(e) whether some of the allottees have requested DDA to give alternative houses in lieu of the ones to be constructed in Sidharth Extension in any other area and under higher category: